are being made to secure additional quotas of copper on the basis of the requirments.

हिन्दी संस्थाओं को अनुदान

5540. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री रमापति राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी संस्थाओं को अनुदान देने के मामले में वित्त मंत्रालय की मंजूरी ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय समान आधार पर ऐसे अनुदान मंजूर करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय हिन्दी संस्थाओं को अपने ही अधिकारों से, समान दर पर, अनुदान देता है । जो प्रस्ताव स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें इस मंत्रालय के पास भेजा जाता है और हर एक मामले के गुण-दोष के आधार पर उसकी जांच की जाती है ।

Kerala N.G.Os.

5540-A. **Shri Vasudevan Nair:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the N.G.O's associations in Kerala state have decided to go on strike following the decisions taken by Government on the Pay Commission's report; and

(b) if so, the steps taken to meet the demand of the N.G.Os?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) There have been some Press reports to this effect.

(b) The /State Government have examined the demands in the light of the available resources and have offered to sanction one increment to all those N.G.Os who get a benefit of less than Rs. 5/- a month as a result of pay fixation and also to sanction one increment to all those with not less than 15 years of service.

Profiteering in Land Prices

5540-B. **Shri Jashvant Mehta:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to bring forward legislation to stop the profiteering in the prices of land surrounding big cities; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The matter is under consideration.

पत्थर तोड़ सहकारी समिति

5540-सी. श्री प० ला० बारूपाल :
श्री तुलाराम :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री मौर्य :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री बागड़ी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने गाजीपुर मार्डन और रामपुरा, नई दिल्ली में सड़क बनाने के लिए पत्थर सप्लाई करने का ठेका भारत सेवक समाज पत्थर तोड़ सहकारी समिति, बॅवर पास, दिल्ली को दिया था।

और पत्थर की सप्लाई भारत सेवक समाज, कनाट प्लेस नई दिल्ली के नाम से की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त ठेके के अन्तर्गत पत्थरों की सप्लाई का खर्च और अपेक्षित श्रमिकों का प्रबन्ध भारत सेवक समाज पत्थर तोड़ सहकारी समिति द्वारा किया गया था किन्तु उसकी आय उस संस्था को नहीं दी गई थी और उसके स्थान पर वह आय भारत सेवक समाज ने ले ली थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) भारत सेवक समाज पत्थर तोड़ सहकारी समिति, खेबर पास, दिल्ली के साथ 1962 में पत्थरों की सप्लाई का कोई ठेका नहीं किया गया था। तथापि, भारत सेवक समाज, कनाट प्लेस नई दिल्ली को कुछ ठेके दिये गये थे तथा 1962-63 के दौरान उनके द्वारा पत्थरों की सप्लाई की गयी थी ।

(ख) क्योंकि सभी ठेके भारत सेवक समाज से किये गये थे अतएव सहकारी समिति के संव्यवहार की सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Welfare of Fishermen in Orissa

5541. Shrimati Akkamma Devi:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Rattan Lal:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Tribal and Rural Welfare Department of the Government of Orissa have forwarded a revised proposal to the Central Government during 1965-66 for execution of the scheme for the welfare of fishermen residing in the coastal belt of Orissa, at a cost of Rs. 2,76,400 and for inclusion of the scheme in the Central Sector under the backward classes welfare programme for cent per cent Central assistance; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) Yes, Sir.

(b) Only a few selected schemes of high priority are included in the Centrally Sponsored Programme of the Backward Classes Sector. Since this scheme is not included in that list it has not been possible to take this up under the Central Sector.

12·10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ENTRY OF ABOUT 1000 ARMED NAGA HOSTILES IN MIZO DISTRICT FROM EAST PAKISTAN

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "लगभग 1000 सशस्त्र नागाओं द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से मीजो जिले में प्रवेश करने के समाचार।"

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Some of us sent short notice questions and so our names also should be included in this.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Sir, we have no information to support the report of entry of 1000 Nagas into Mizo Hills District from Pakistan. According to our information, no large gang of Nagas has gone into Pakistan in recent months. There are reports